

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक / / मार्च, 2013

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना  
“टी0एच0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित योजना” में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-1471/3-3(टी.एच.डी.सी.) दिनांक 08 फरवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की राजस्व पक्ष की योजना “टी0एच0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित योजना” हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आय-व्ययक प्रावधान (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या-1220/X-2-2012-12(41)2006 दिनांक 14 अगस्त, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 7.50 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में ₹ 41,20,000/- (₹ इकतालीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 तथा शासनादेश सं0-607/XXVII(1)/2013, दिनांक 01 जनवरी, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनार्य एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.



6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
13. टी०एच०डी०सी० से प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त की जाने वाली समस्त धनराशि प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर ली जाय, अग्रेत्तर धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब टी०एच०डी०सी० से प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त हो चुकी हो।
14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1303270107 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 11 टी.एच.डी.सी. सहायतित योजना 1101 टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जाएगा। इस प्रयोजन हेतु आन लाईन बजट आवंटन की हार्ड कापी भी संलग्न की जा रही है:-



लेखा शीर्षक/योजना का नाम	आय-व्ययक 2012-13 (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित)	पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृति	शेष आय-व्ययक	वर्तमान स्वीकृति
अनुदान सं०-27 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 1101-टी०एच०डी०सी० द्वा वित्त पोषित योजना				
25-लघु निर्माण	5600	0	5600	0
26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संचयन	1	0	1	0
29-अनुरक्षण	6000	750	5250	4120
42-अन्य व्यय	500	0	500	0
योग	12101	750	11351	4120

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ इकतालिस लाख बीस हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं०-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 तथा शासनादेश सं०-607/XXVII(1)/2013, दिनांक 01 जनवरी, 2013 में वर्णित प्राविधान/दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)  
अपर सचिव

संख्या- <sup>526</sup> (1)/X-2-<sup>2013</sup> 2012, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)  
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - S1303270107

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1303270107

आवंटन पत्र दिनांक - 08-Mar-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी  
800 - अन्य व्यय 11 - टी0एच0डी0सी0 सहायक योजना  
01 - टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना

Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
29 - अन्वक्षण	750000	4120000	4870000
	750000	4120000	4870000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

4120000

